Nothing Like Voting, I Vote for Sure
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय
OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
Andaman and Nicobar Islands
e-Mail ID : ceo_andaman@eci.gov.in / ceoandamans@gmail.com
Phone : 03192-234703 / 231496

*****

F.No.5/52/Elect/2010/ 66 Port Blair, dated the 12 March 2025

To

The Director,
Information, Publicity & Tourism,
Sri Vijaya Puram

निदेशक (सू.प्र.प) का निजी अनुभाग
Pers. Section of Director (IP&T)
प्रा. प्रे .स / R.D. No...1842
दिनांक / Date 13/03/25

Sub:- Elections- Press release of Election Commission of India dated 11.03.2025 – Publication in local media - regarding.

Sir,

I am to enclosing herewith the ECI's Press release in English & Hindi and request you to kindly make necessary arrangement for wider outreach in all print/electronic media on 13.03.2025 as news item in all Districts.

Further, it is requested to send a complied coverage in single pdf file for the news items appeared in the dailies to this office for further submission to ECI on 13.03.2025.

Yours faithfully

Encl:A/A

(Vinayak Chamadia, IAS)
Dy. Chief Electoral Officer
A & N Islands

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. ECI/PN/192/2025 11.03.2025

Press Note

EC invites Party Presidents and senior leaders for interaction to further strengthen electoral processes within legal framework

The Election Commission of India has invited suggestions from all National and State political parties by April 30, 2025 for any unresolved issues at the level of ERO, DEO or the CEO, as the case may be. In an individual letter issued to political parties today, the Commission also envisaged an interaction with the Party Presidents and senior members of the party, at a mutually convenient time, to further strengthen electoral processes in accordance with the established law.

Earlier, during an ECI conference last week, Chief Election Commissioner Shri Gyanesh Kumar had instructed CEOs, DEOs and EROs of all States/UTs to hold regular interactions with political parties, resolve any suggestions received in such meetings strictly within the legal framework already in place and submit an action taken report to the Commission by March 31, 2025. The Commission also urged political parties to proactively use this mechanism of decentralised engagement.

Political parties are one of the key stakeholders amongst 28 stakeholders identified by the Commission as per the Constitution and statutory framework covering all aspects of electoral processes. The Commission in its letter to political parties also noted that Representation of the People Act 1950 & 1951; Registration of Electors Rules, 1960; Conduct of Election Rules, 1961; orders of Hon'ble Supreme Court and Instructions, Manuals and Handbooks issued by Election Commission of India from time to time (available on ECI website) have established a decentralised, robust and transparent legal framework for holding free and fair elections.

Anuj Chandak

Director

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. ईसीआई/पीएन/192/2025

11.03.2025

प्रेस नोट

निर्वाचन आयोग ने कानूनी ढांचे के भीतर चुनावी प्रक्रियाओं को और मजबूत करने के लिए राजनीतिक दलों के अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं को बातचीत के लिए आमंत्रित किया

भारत निर्वाचन आयोग ने सभी राष्ट्रीय और राज्यीय राजनीतिक दलों से 30 अप्रैल, 2025 तक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ), जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) या मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ), जैसा भी मामला हो, के स्तर पर किसी भी अनसुलझे मुद्दे के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं। आज राजनीतिक दलों को जारी एक व्यक्तिगत पत्र में, आयोग स्थापित कानून के अनुसार चुनावी प्रक्रियाओं को और मजबूत करने के लिए आपसी सहमति से निर्धारित सुविधाजनक समय पर राजनीतिक दलों के अध्यक्षों और वरिष्ठ सदस्यों के साथ बातचीत करने पर भी विचार कर रहा है।

इससे पहले, पिछले सप्ताह हुए सम्मेलन के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने सभी राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के सीईओ, डीईओ और ईआरओ को राजनीतिक दलों के साथ नियमित बातचीत करने, ऐसी बैठकों में प्राप्त सुझावों को पहले से मौजूद कानूनी ढांचे के भीतर ही समाधान करने और आयोग को कार्रवाई रिपोर्ट 31 मार्च, 2025 तक प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। आयोग ने राजनीतिक दलों से विकेंद्रीकृत रूप से संबद्ध रखने के इस तंत्र का सक्रिय रूप से उपयोग करने का भी आग्रह किया।

राजनीतिक दल संविधान और चुनावी प्रक्रियाओं के सभी पहलुओं को कवर करने वाले सांविधिक ढांचे के अनुसार आयोग द्वारा पहचाने गए 28 हितधारकों में से एक प्रमुख हितधारक हैं। आयोग ने राजनीतिक दलों को लिखे अपने पत्र में इस बात पर भी ध्यान दिलाया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951; निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960; निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961; माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों और आयोग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों, मैनुअलों और हैंडबुकों (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध) से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक विकेंद्रीकृत, सुदृढ़ और पारदर्शी कानूनी ढांचे का निर्माण हुआ है।

ह./-
अनुज चांडक
निदेशक